# बंगाल में द्वैध शासन

# Dual Government in Bengal

- क्लाइव ने बंगाल में दूसरी गवर्नरी प्राप्त होते ही बंगाल में द्वैधशासन प्रणाली की व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था । क्लाइव ने यह प्रशासनिक व्यवस्था बंगाल में 1765 ईसवी में लागू किया । क्लाइव की इस प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार तथा अधिकार रहित उत्तरदायित्व था ।
- 12 अगस्त 1765 के फरमान के अनुसार शाह आलम ने 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले दीवानी का भार कंपनी को सौंप दिया था तथा कंपनी को 53 लाख रुपये निजामत के कार्य के लिए बंगाल के नवाब को देने थे, शेष बचे हुए भाग को अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र थी।
- दीवान तथा निजाम की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को मिला। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए शिताब राय को नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खां को उप निजाम के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार समस्त दीवानी एवं निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता रहा। द्वैध शासन व्यवस्था में नियुक्ति से संबंधित तथा नीति निर्माण से संबंधित सारी शक्तियां ब्रिटिश के पास थी जबकि उत्तरदायित्व भारतीयों के पास यह व्यवस्था ही दोहरी शासन प्रणाली या द्वैध शासन कहलाई जिसका सीधा तात्पर्य था, दो राजे कंपनी तथा नवाब | एक के हाथ में शक्ति थी तो दूसरे के हाथ में उत्तरदायित्व

**दुवैध शासन प्रणाली लागू करने के कारण :-** क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया मात्र है। उसने प्रवर समिति (Select Committee) को लिखा था कि यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके पक्ष में उसने निम्नलिखित कारण दिए -

1. यदि कंपनी स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता हाथ में ले लेती है तो उसका वास्तविक रूप लोगों के सम्मुख आ जाएगा और संभवत सारे भारतीय इसके विरोध में एकत्रित हो जाएंगे,
2. संभवत फ्रांसीसी, डच तथा डेन जैसी विदेशी कंपनियां सुगमता से कंपनी की सूबेदारी को स्वीकार नहीं करेगी तथा कंपनी को वे कर इत्यादि नहीं देगी जो नवाब के फरमानों के अनुसार उन्हें देने होते थे।
3. स्पष्ट राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने से इंग्लैंड तथा विदेशी शक्तियों के बीच कटुता आ जाती और संभवत यह सभी शक्तियां इंग्लैंड के विरुद्ध एक मोर्चा खड़ा कर ले जैसा कि 1778-80 के बीच अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ।
4. तत्कालीन समय में इंग्लैंड के पास ऐसे प्रशिक्षित अधिकारी भी नहीं थे जो शासन का भार संभाल लेते। जो थोड़े बहुत लोग कंपनी के पास थे भी वे भारतीय रीति-रिवाजों तथा भाषा से अनभिज्ञ थे।
5. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस समय समस्त प्रदेश को ले लेने के पक्ष में नहीं था क्योंकि इससे कंपनी के व्यापार में बाधा पड़ने की संभावना थी। वे लोग प्रदेश के स्थान पर धन में अधिक रुचि रखते थे।

6. क्लाइव यह भी समझता था कि यदि वह बंगाल की राजनीतिक सत्ता हाथ में ले लेता है तो संभवत अंग्रेजी संसद कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देगी।.

## दुवैध शासन प्रणाली से कंपनी को लाभ :-

1. कंपनी का बंगाल की सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया जबकि उनके पास किसी प्रकार के जवाबदेही नहीं थी ।
2. अब शासन की विफलताओं के लिए भारतीयों पर दोषारोपण किया जा सकता था जबकि इससे प्राप्त लाभों का उपयोग कंपनी करती थी।

**द्वैध शासन प्रणाली के दुष्परिणाम :-** प्रशासन की जो व्यवस्था क्लाइव ने स्थापित की थी वह अप्रभावी तथा अव्यावहारिक थी। इससे बंगाल में अराजकता तथा भ्रांति फैला । इसके निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आए -

1. निजामत की शिथिलता के कारण देश में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो गए। नवाब में कानून लागू करने एवं न्याय देने की सामर्थ नहीं रही थी। कंपनी प्रशासन के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करती थी। ऐसी अव्यवस्था में बंगाल वासियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा।
2. द्वैध शासन से कृषि का हास हुआ। भूमि कर संग्रह करने का अधिकार प्रतिवर्ष अधिकाधिक बोली देने वाले को दिया जाता था जिसका कृषि विकास में स्थाई रुप से कोई रुचि
3. नहीं थी । प्रत्येक वर्ष लगान की राशि बढ़ती चली जाती थी। तंग आकर कृषकों ने खेती करना छोड़ दिया और लगान इतनी कड़ाई से वसूल होता था कि किसानों को अपनी संपदा गिरवी रखकर और बच्चे बेचकर लगान चुकाना पड़ता था। स्वभाविक रुप से ऐसी स्थिति में किसानों की खेती में दिलचस्पी कम हो गई।
4. ऐसे में 1770 ईस्वी में अकाल का पड़ना और कंपनी की तरफ से जनता की सहायता का कोई प्रयत्न नहीं करना अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रतिकूल साबित हुआ । इस स्थिति में भी कंपनी के कर्मचारियों ने वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर ज्यादा लाभ कमाया।
5. आर्थिक अव्यवस्था की स्थिति तथा कृषि के चौपट होने से व्यापार वाणिज्य की भी बुरी अवस्था हो गई। कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार एवं धन प्राप्ति की लालसा से उनकी व्यक्तिगत आय में तो वृद्धि हुई किंतु बंगाल की दशा कंगाल हो गई ।
6. कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया फलतः वह बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और उसे विदेशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाभ में समझा जाता था। इसी प्रक्रिया में 1766-67 और 68 ईसवी में बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड की निकासी हुई। इस द्वैध शासन का दुष्परिणाम यह हुआ कि बंगाल से धन निकासी के फल स्वरुप यह प्रांत दरिद्र हो गया।
7. द्वैध शासन ने उद्योग धंधों को भी नष्ट कर दिया। बंगाल के कपड़ा उद्योग को अत्यधिक हानि हुई। कंपनी ने बंगाल के रेशम उद्योग को निरुत्साहित करने का प्रयत्न किया क्योंकि इससे इंग्लैंड के रेशम उद्योग को क्षति पहुंचती थी।
8. देसी कारीगरों को इतना परेशान किया गया कि वह व्यवसाय छोड़कर सन्यासी या डाकू बन गए। जुलाहों ने अपने अंगूठे कटवा लिए ताकि उन्हें कंपनी के लिए वस्त्र तैयार ना करना पड़े । फलतः बंगाल के कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया।
9. द्वैध शासन के कारण बंगाली समाज का नैतिक पतन भी आरंभ हो गया। कृषकों ने अनुभव किया कि यदि वह अधिक उत्पादन करता है तो उसे अधिक कर देने पड़ेंगे अतएव केवल गुजारा भर उत्पादन करना सही है। उसी प्रकार जुलाहा जिसे यह आभास हो चला था कि परिश्रम का लाभ वह भोग नहीं सकता इस कारण से वह उत्तम कोटि का उत्पादन करने के प्रति दृढ़ नहीं था। इस प्रकार बंगाल की कार्य संस्कृति भी द्वैध शासन के कारण प्रभावित हुई ।

   द्वैध शासन के दुष्परिणामों के संदर्भ में सर जॉर्ज कॉर्नवाल ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस में कहा था कि 'मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं था।'

# Dual Government In Bengal

- As soon as Clive got the second governorship in Bengal, he implemented the system of diarchy in Bengal. Under this system, the real power was with the Company but the burden of administration was on the shoulders of the Nawab. Clive implemented this administrative system in Bengal in 1765 AD. The main feature of this administrative system of Clive was authority without responsibility and responsibility without authority.
- According to the decree of 12 August 1765, Shah Alam had handed over the responsibility of Diwani to the Company in exchange of Rs 26 lakh annually and the Company had to give Rs 53 lakh to the Nawab of Bengal for the work of Nizamat, the remaining part was to be kept with itself. Was free to keep.
- The Company got the right to appoint Diwan and Nizam. The Company appointed two Deputy Diwans for civil work, Mohammad Raza Khan for Bengal and Shitab Rai for Bihar. Mohammad Raza Khan was appointed as Deputy Nizam. In this way, all the civil and Nizamat work continued to be done by Indians only. In the dual government system, all the powers related to appointment and policy making were with the British, while the responsibilities were with the Indians. This system itself was called dual government system or dual rule, which directly meant, two kings, the company and the Nawab. One had power and the other had responsibility.

Dual Government In Bengal

**Due to implementation of diarchy system :-** Clive believed that all the power was with the Company and the Nawab had only a shadow of power. He had written to the Select Committee that this name, this shade is necessary and we should accept it. He gave the following reasons in favor of this -

1. If the Company clearly takes over political power then its true form will be revealed to the people and probably all Indians will gather against it,
2. Probably the foreign companies like French, Dutch and Danes would not easily accept the company's suzerainty and would not pay the company the taxes etc. which they had to pay as per the orders of the Nawab.

3. Taking over clear political power would have led to bitterness between England and foreign powers and possibly all these powers would have formed a front against England as happened during the American War of Independence between 1778-80.
4. At that time, England did not even have such trained officers who could take charge of the administration. Even the few people who were with the company were ignorant of Indian customs and language.
5. The Court of Directors was not in favor of taking over the entire territory at that time because it was likely to hinder the company's business. They were more interested in money rather than territory.
6. Clive also understood that if he took over the political power of Bengal then probably the English Parliament would start interfering in the work of the Company.

## Company benefits from dual governance system :-

1. The Company had complete control over the power of Bengal while they did not have any kind of accountability.
2. Indians could now be blamed for the failures of governance while the Company enjoyed the profits.

**ill effects of dual government system :-** The system of administration established by Clive was ineffective and impractical. This spread anarchy and confusion in Bengal. The following side effects emerged -

1. Due to the laxity of the Nizamat, the law and order situation in the country became weak. The Nawab no longer had the power to enforce laws and deliver justice. The company did not accept the responsibility of administration. The people of Bengal had to suffer a lot in such chaos.
2. Agriculture declined due to dual rule. The right to collect land tax was given every year to the highest bidder who had any permanent interest in agricultural development.
3. Wasn't. The amount of tax kept increasing every year. Fed up, the farmers gave up farming and the rent was collected so strictly that the farmers had to pay the rent by mortgaging their property and selling their children. Naturally, in such a situation, farmers' interest in farming decreased.
4. In such a situation, the famine in 1770 AD and the company not making any efforts to help the people proved to be unfavorable from the economic point of view. Even in this situation, the company employees earned more profit by increasing the prices of the goods.
5. Due to economic chaos and collapse of agriculture, trade and commerce also became bad. Due to the corruption of the company employees and their greed for wealth, their personal income increased but the condition of Bengal became poor.
6. The Company stopped sending money from England to buy Indian goods, as a result, they bought Indian goods from the revenue received from Bengal and sold them abroad. This money was considered as the cost capital of the company and was considered in the profit of the company. In this process, about 57 lakh pounds were withdrawn from Bengal in 1766-67 and 68 AD. The adverse effect of this dual rule was that the province became poor as a result of the withdrawal of money from Bengal.

7. Dyarchy also destroyed industries. The textile industry of Bengal suffered huge losses. The Company tried to discourage the silk industry of Bengal because it caused damage to the silk industry of England.
8. Native artisans were harassed so much that they left the business and became ascetics or dacoits. The weavers got their thumbs cut so that they would not have to prepare clothes for the company. As a result, the cottage industries of Bengal were destroyed.
9. Due to dual rule, the moral decline of Bengali society also started. Farmers realized that if they produced more, they would have to pay more taxes, so it was better to produce just enough to survive. Similarly, the weaver who had realized that he could not enjoy the benefits of his hard work, was therefore not determined to produce good quality produce. Thus, the work culture of Bengal was also affected due to dual rule. I

   Regarding the ill effects of dual rule, Sir George Cornwall had said in the British House of Commons that 'I can say with certainty that in any civilized country of the world there was no government more corrupt, false and bad than the government of the East India Company till 1765-84. was not.'